2002-03 में उडीसा को आर.ई.सी. के माध्यम से कितना धन दिया गया है एवं 2002-03 में पी.एम.जी.वाई. के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उडीसा को कितना धन दिया गया है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, लगभग 78 हजार विलेजेज हैं जिनमें अभी बिजली जानी हैं। ये अन-इलेक्ट्रीफ़ाइड विलेजेज हैं और राज्य सरकारों को बार-बार ये सूचनाएं दी जाती हैं और सहायता भी दी जाती है कि हमारा लक्ष्य 2007 तक हर गांव में बिजली देने का है। सभापति जी, माननीय सदस्य ने उडीसा के बारे में कहा, वह सत्य है कि 9776 गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इन गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए रुरल इलेक्ट्रिफ़िकेशन कॉपोरेशन के माध्यम से हम राज्यों को लोन के रुप में सहायता देते हैं और भारत सरकार की अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से भी ग्रामीण विद्युतीकरण किया जाता है। आप ने उडीसा के संदर्भ में पूछा है, एम.एन.पी. के माध्यम से 2001-02 में 11.33 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पी.एम.जी.वाय. के तहत 17 करोड़ 3 लाख रुपए दिए गए हैं। इस तरह कुल 28 करोड़ 36 लाख रुपए उडीसा को दिए गए है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, actually, my supplementary pertains to the earlier question. So, I request the Minister not to say that this is not relevant. Sir, the Minister has stated the reason as to why the States in the Southern region are unable to draw the allocated supply. Andhra Pradesh has requested for restoration of 40 per cent from the unallocated units... *(Interruptions)* Yes; that was the request of the Government of Andhra Pradesh. It had asked for restoration of the share of Andhra Pradesh from unallocated power of the Central Power Generating Stations in the Southern Region from 40 per cent to 28 per cent... You have stated so many reasons. In spite of drought, in spite of lack of water in the reservoirs, — we have to bellow the water from 600 feet deep to save the crops — we are unable to purchase power from the Central pool because of prohibitive prices. I would like to know whether the Government would, at least, consider the request of the Government of Andhra Pradesh and other Southern States so that power can be supplied, during difficult times, like, drought, at a reasonable rate of interest.

Development of Controlled Shunt Reactor (CSR) for Power Transfer

*307. SHRI B.J. PANDA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) has developed a unique device, called "Controlled Shunt Reactor (CSR)" the first of its kind in the world, for improving power transfer capability and reducing transmission losses;

(b) whether it is a major breakthrough for the country's power transmission sector and whether this has been commissioned at Power Grid, Itarsi in Madhya Pradesh, as reported in the Hindustan Times dated the 22nd December, 2002; and

(c) the places where it is now proposed to be installed?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) According to the information received from Bharat Heavy Electricals Ltd., (BHEL) and Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL), a prototype of "Controlled Shunt Reactor (CSR)" has been developed by BHEL. This CSR can be used selectively depending upon the system configuration and power system requirement. It aims to provide full reactive support to the lines during energisation and facilitate reactive power management in Extra High Voltage (EHV) power transmission system. The CSR is a significant development in the field of High Voltage Power Transmission as the use of this equipment is meant to improve the voltage profiles and reduce transmission losses. A prototype CSR of 50 MVAR capacity, 420 KV class developed by BHEL has been installed at 400 KV Itarsi sub-station of POWERGRID in September, 2001.

(c) The requirement of CSR in the EHV system is mainly for controlling over-voltage where very fast control switching of reactor is desirable. Extensive studies are carried out to determine the size of the CSR and its location in the system, keeping in view its cost and requirement. Actual deployment of the CSR will depend on techno-economic considerations.

SHRI BJ. PANDA: Sir, the number one bottleneck in solving power problem in tne country is not the requirement for generating capacity but the requirement in improving the efficiency in transmission and distribution. In this context, the hon. Minister has stated in his answer that the

development of this Controlled Shunt Reactor is particularly relevant for high voltage transmission lines. Sir, this is very important for States like Orissa and other States in the Eastern Region, which have coal fields, because that is where naturally power plants ought to be set up. But it is ironic that even today, power plants have been set up thousands of kilometres away. Because the transmission is not efficient, and that is why, it becomes even economical to import coal and set up power plants in other parts of the country. Sir, the hon. Minister has stated that the deployment of technology is *\\ke\y...(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Mr. Panda, you should put direct question.

SHRI B.J. PANDA: Sir, I am putting the question.The deployment of this, will depend upon techno-economic feasibility. Can he give us a timeframe when such feasibility will be studied and committed?

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, यह प्रश्नकाल पावर का प्रश्नकाल बन गया है।

श्री सभापति: महिलाओं का प्रश्नकाल हो गया है।

श्री सुरेश पचौरी: वे भी पावर हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए,नाम लेते ही पावर पैदा हो गई।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): वह भी शक्ति है, सर। महिला भी शक्ति है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते:सर, यह कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर, जिसका निर्माण बीएचईएल ने किया है, प्रायोगिक तौर पर पावरग्रिड ने इसको इटारसी में लगाया है। इसके परिणाम अच्छे हैं, लेकिन इस पर होने वाले खर्च, इसकी लागत का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। इसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं,इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए यह कहा गया है कि इसको आवश्यकता, इसकी तकनीकी क्षमता और इस पर आने वाले खर्च को देखते हुए इसको उपयोग में लाने का निर्णय हमने किया है। इस प्रकार से जहां -जहां आवश्यकता होगी, निश्चत रुप से वहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं।

श्री जयन्ती लाल बरोट: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि बिजली उत्पादन को सरकारी क्षेत्र में करने की बजाए क्या मंत्री जी प्राइवेट सैक्टर को देना चाहते हैं और नान कन्वेंशल ऊर्जा पैदा करने के लिए क्या आपके पास कोई पेंडिंग दरख्वास्त हैं?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सर, पावर जनरेशन में तो आज हम निजी क्षेत्र में है। कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग-अलग राज्यों में निजी क्षेत्र के लगे हुए हैं और भविष्य में भी यदि कोई निजी क्षेत्र पावर जनरेशन में आगे आना चाहते है तो उसके लिए सरकार की ओर से पूरी सहायता की जाएगी।

श्री जयन्ती लाल बरोट:सभापति जी, मैं यह जानना...

श्री सभापति:बस हो गया, बैठिए।

मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि बिजली में ट्रांसमिशन लासिज 24,000 करोड़ रुपए के है। इनको रोकने का यदि प्रयत्न किया जाए तो इस बिजली की समस्या का बहुत हद तक समाधान हो सकता है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, मैं आपके मत से सहमत हूँ। लगभग 30,000 करोड़ रुपए का घाटा है और इसको बचाने के लिए प्रयास केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग योजनाओं के तहत किए जा रहे हैं और निश्चित रुप से इससे हमें राहत मिल सकती है।

कोकिंग कोयले का उत्पादन

*308. **श्री कपिल सिम्बल**:††
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि देश में कोकिंग कोयले का उत्पादन गत वर्षों से लगातार कम होता जा रहा है;

(ख़) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान यह उत्पादन कितना था;

(ग)चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कोयले के उत्पादन की मात्रा के संबंध में क्या आकलन है; और

(घ)उत्पादन में निरंतर कमी आने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कडिया मुंडा) (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

---

†† सभा में यह प्रश्न श्री कपिल सिब्बल द्वारा पूछा गया।